भारत में तीव और गंभीर बीमारियां

(फैलाव और उपचार की स्थिति)

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2011–12
के सन्दर्भ में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च और बीमारियों
के दायरे का एक आंकलन

विकास संवाद

भारत में बीमारियां

देश की आर्थिक वृद्धि दर कुछ भी रही हो, परन्तु यह लोगों को बुनियादी और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कर पाने में अब तक सफल साबित नहीं हुई है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना बनाये जाने के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के मुताबिक, योजना आयोग के द्वारा भारत सरकार को यह सलाह देनी चाहिए कि वह किसी और क्षेत्र के मुकाबले सबसे ज्यादा और सबसे पहले स्वास्थ्य के ढांचे में निवेश करे। देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत हिस्सा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्च होना चाहिए, परन्तु सरकार केवल 1.2 प्रतिशत ही खर्च कर रही है। इसका असर लोगों पर बहुत गहरा पड़ता है।

खर्च बढ़ाना क्यों जरूरी है ?

भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा बच्चे अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले मर जाते हैं।

सबसे ज्यादा मातृत्व मौतें यहां होती हैं।

दुनिया के आधे कुष्ठ रोगी (130 हजार) और 21 प्रतिशत टीबी के रोगी (19 लाख) यहां हैं।

प्रति व्यक्ति दवाओं पर आवंटन

सालभर में प्रति व्याक्ति 43 रुपए की दवाएं! इसके बावजूद भारत सरकारों ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बेहद गैर–अधिकार मूलक रवैया अपनाया है। वर्ष 2011 की स्थिति में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति लगभग 2500 रुपए का कुल खर्च है। इसमें से सरकार केवल 675 रुपए खर्च कर रही है। बाकी 1825 रुपए लोग अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं और यह लोगों को कर्जदार बनाने में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2011 की स्थिति में दवाओं के लिए प्रति व्यक्ति सालाना केवल 43 रुपए आवंटित किया जा रहा था, जबकि केवल 5.4 प्रतिशत लोगों को ही मुफ्त दवाइयां मिल पा रही थीं। प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को केवल मजबूत बनाने के लिए देश को 24.7 लाख डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जरूरत है। वैसे अगर पूरा ढांचा खड़ा करना हो तो 6.26 लाख डॉक्टरों सहित 49.69 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों की जरूरत है। पिछले केंद्र सरकार 5 बजट प्रस्तावों से पता चलता है कि कि क्या सरकार वास्तव में स्वास्थ्य के अधिकार के सन्दर्भ में प्रतिबद्ध है? योजना आयोग की रिपोर्ट बताती है कि देश में 187 मेडिकल कालेजों, 383 नर्सिंग स्कूलों और 232 एएनएम स्कूलों की जरूरत है। फिर भी सरकार ने ढांचागत कर्मियों को दूर करने की कोई इच्छाशक्ति नहीं दिखाई है। इतना ही नहीं, बारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह प्रयास करने का निश्चय किया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं का भरसक निजीकरण हो।

फरवरी 2012 में भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन ''राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय'' ने देश में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के पारिवारिक उपभोग पर एक रिपोर्ट (संख्या 541) जारी की। यह रिपोर्ट बताती है कि गांव का एक व्यक्ति हर महीने अपने जीवन पर 1053.64 रुपए यानी रोजाना लगभग 35 रुपए खर्च करता है। इसमें से 600.36 रुपए अर्थात लगभग 57 प्रतिशत केवल भोजन की जरूरत को पूरा करने में ही खर्च हो जाता है। शहरों में रहने वाले लोग 1984.46 रुपए प्रति माह यानी लगभग 66.14 रुपए प्रतिदिन खर्च करते हैं। इसमें से 880.83 रुपए (44.38 प्रतिशत) भोजन की जरूरत को पूरा करने में खर्च होता है। पेट भरना सबसे पहला और सबसे खर्चीला काम है। मानव विकास के कुछ चुनिन्दा आधारों में शिक्षा और सूचना भी शामिल हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में किताबों और पत्रिकाओं पर प्रति व्यक्ति 5.87 रुपए और शहरों में 14.50 रुपए खर्च हो रहे हैं। चूंकि राज्य का ढांचा शिक्षा और स्वास्थ्य तंत्र का

गुणवत्तापूर्ण तरीके से लोकव्यापीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए लोगों को भोजन के बाद सबसे ज्यादा खर्च इन्हीं दो चीजों पर करना पड़ रहा है। गांव में शिक्षण और अन्य शुल्क चुकाने में 21.48 रुपए (कुल व्यय का 2.038 प्रतिशत) और शहरों में 106.81 रुपए प्रतिमाह (कुल व्यय का 5.38 प्रतिशत) का खर्च लोग अपने खाते से करने पर मजबूर हैं। अकेले दवाओं पर गांवों में 40.59 रुपए (कुल व्यय का 3.58 प्रतिशत) और शहरों में 62.05 रुपए (कुल व्यय का 3.12 प्रतिशत) हर माह खर्च हो रहे हैं। इसमें भी विभिन्न प्रदेशों असमानता का आलम यह है कि केरल में दवाओं पर खर्च 125.63 रुपए, गोवा में 108.49 रुपए और पुडुचेरी में 110.71 रुपए है, तो झारखंड में 33.98 रुपए, असम में 29.25 रुपए, बिहार में 40.98 रुपए ही खर्च हो पा रहा है। इन हालात में सरकार की नीतिगत प्राथमिकता यह नहीं हो सकती है कि वह भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य को निजी हाथों में सौंपने की नीति बनाए। हमारा संविधान जीवन जीने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देता है। तीनों सेवाएं इस मौलिक अधिकार का अहम हिस्सा हैं। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने ही नहीं, बल्कि संसद ने भी कई बार परिभाषित किया है।

इलाज तो होता है, सरकारी न मिले तो जेब से ही सही

सरकार के वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2011–12) की रिपोर्ट बताती है कि देश के वंचित राज्यों में प्रति एक लाख जनसंख्या पर साधारण और गंभीर बीमारियों से प्रभावित लोगों की संख्या कितनी है। साधारण बीमारियों में डायरिया, बुखार, तीव्र श्वसन संक्रमण और गंभीर बीमारियों में तपेदिक, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, आर्थ्राइटिस या गठिया और डायबिटीज शामिल हैं। इस रिपोर्ट में से हमने मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ, उड़ीसा के आंकड़ों को निकालकर तुलनागत अध्ययन किया। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2011–12 प्रति एक लाख की जनसंख्या पर अलग–अलग बीमारी से प्रभावित जनसंख्या का अनुपात बताता है। इसी अनुपात को हमने वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों से जोड़कर देखने की कोशिश की। फिर उसी जनगणना के आंकड़ों के साथ गुणा–भाग करके बीमारियों से प्रभावित लोगों की कुल संख्या जानने की कोशिश की।

यह विश्लेषण हमें बताता है कि विभिन्न बीमारियों से प्रभावित लोग अपना इलाज करवा रहे हैं या नहीं? अगर हां तो कितने लोग सरकारी इलाज ले रहे हैं? रिपोर्ट सरकार की उस धारणा को झुठलाती है, जो यह प्रचारित करती है कि लोग अंधविश्वासी हैं, केवल झाडफूंक में विश्वास रखते हैं और वैज्ञानिक इलाज नहीं करवाते। वास्तव में ज्यादातर लोग इलाज करवाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि सरकारी इलाज न मिलने पर वे निजी सेवाओं की शरण लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

तीव्र और स्थायी बीमारियों का फैलाव और उनके उपचार से सम्बंधित व्यवहार

तीव्र और अक्सर होने वाली बीमारियों की स्थिति और उनका इलाज

डायरिया : मध्यप्रदेश में हर एक लाख की जनसंख्या पर 728 लोग डायरिया से पीड़ित पाए गए। यदि ग्रामीण और शहरी सन्दर्भ की बात की जाए तो पता चलता है कि शहरों में एक लाख की जनसंख्या पर 500 और ग्रामीण क्षेत्रों में 836 लोग इससे पीड़ित होते हैं। अन्य राज्यों से तुलना करने पर हमें पता चलता है कि उत्तरप्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर 792 (ग्रामीण 831 और शहरी 655), राजस्थान में कुल 420 (ग्रामीण क्षेत्रों में 408 और शहरी क्षेत्रों में 455), झारखंड में 371 (ग्रामीण में 369 और शहरी में 376) लोग डायरिया से पीड़ित पाए जाते हैं। ज्यादा प्रभावित राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ है। जहां एक लाख की जनसंख्या पर 903 और बिहार में 1900 लोगों को डायरिया ने जकड़ा। उड़ीसा में तुलनात्मक रूप से कम (592 प्रति लाख) लोग डायरिया से प्रभावित पाए गए।

तीव्र श्वसन संक्रमण : मध्यप्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर 1572 लोगों पर तीव्र श्वसन संक्रमण का असर पाया गया, जबकि उत्तरप्रदेश में यह अनुपात बहुत ज्यादा (6362 प्रति लाख) पाया गया। राजस्थान में 1186, झारखंड में 3142, उड़ीसा में 1252, छत्तीसगढ़ में 3396, उत्तराखंड में 2000 और बिहार में 4199 लोग इससे ग्रसित पाए गए।

किसी भी तरह का बुखार – मध्यप्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर 6391 लोग किसी न किसी तरह के बुखार से पीड़ित पाए गए। उत्तरप्रदेश में 4352, राजस्थान में 2776, झारखंड में 3390, उड़ीसा में 6403, छत्तीसगढ़ में 6928, उत्तराखंड में 5843, बिहार में 7421 लोग किसी न किसी तरह के बुखार से ग्रसित पाए गए।

किसी न किसी तरह की तीव्र बीमारी (बुखार, श्वास संक्रमण और डायरिया) का विस्तार: वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक उत्तरप्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर 12050 लोग, बिहार में 14178 लोग, छत्तीसगढ़ में 11646 लोग किसी न किसी तरह की तीव्र बीमारी से ग्रसित पाए गए, जबकि उत्तराखंड में यह अनुपात 8539, उड़ीसा में 9632, मध्यप्रदेश में 9177, राजस्थान में 5300 और झारखंड में 7397 पाया गया।

इलाज की स्थिति : उल्लेखनीय है कि इन बीमरियों से पीड़ित लोग अब केवल झाड–फूंक या अंधविश्वास में फंसे हुए नहीं माने जा सकते हैं। वे सही और वैज्ञानिक उपचार चाहते हैं। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण बताता है कि मध्यप्रदेश में किसी भी तीव्र बीमारी से पीड़ित 92.5 प्रतिशत लोग इलाज करवाते हैं, परन्तु केवल 18.7 प्रतिशत ही सरकारी स्रोत से सेवा हासिल करते हैं। उत्तरप्रदेश में 98.1 प्रतिशत लोग बाकायदा उपचार करवाते हैं, सरकारी स्रोत से इलाज करवाने वाले केवल 4.6 प्रतिशत हैं। राजस्थान में 95.8 प्रतिशत लोग इलाज करवाते हैं, सरकारी स्रोत से इलाज करवाने वाले यहां थोड़े ज्यादा (39.9 प्रतिशत) हैं। झारखंड में 89.2 प्रतिशत लोग इलाज करवाते हैं। सरकारी स्रोत से केवल 9.7 प्रतिशत लोग ही इलाज करवाते हैं। उड़ीसा में 96.3 प्रतिशत लोग अपने दम पर इलाज करवा रहे हैं और सरकारी स्रोत से इलाज कराने वालों का प्रतिशत 55.3 है। छत्तीसगढ़ में भी लोग जिम्मेदारी से इलाज करवाते हैं। वहां 98.9 प्रतिशत लोग अपने दम पर इलाज करवाते हैं जबकि 30.6 प्रतिशत लोग सरकारी स्रोतों से इलाज करवाते हैं। लगभग इसी तरह की स्थिति उत्तराखंड और बिहार में भी हैं। जहां क्रमशः 98.9 प्रतिशत (15.3 प्रतिशत सरकारी व्यवस्था में) और 98.2 प्रतिशत (4.8 प्रतिशत सरकारी व्यवस्था में) लोग इलाज करवाते हैं।

लंबी और स्थायी बीमारियों की स्थिति और उनका इलाज

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में दूसरा हिस्सा उन बीमरियों का है जो लंबी और स्थाई बीमरियां मानी जाती है – जैसे उच्च रक्तदाब (हृदय रोग), तपेदिक, अस्थमा, आर्थराईटिस और गठिया शामिल हैं। यह सर्वेक्षण देखता है कि भारत के कुछ चुने हुए राज्यों में इन बीमारियों का फैलाव कितना है और लोग उनका इलाज करवाते हैं या नहीं, यदि इलाज करवाते हैं तो कहां?

डायबिटीज यानी मधुमेह : मध्यप्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर 385 लोगों (ग्रामीण 172 और शहरी 834) को मधुमेह की बीमारी है। उत्तरप्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर 414, राजस्थान में 345, झारखण्ड में 683 उड़ीसा में 741, छतीसगढ़ में 595,

उत्तराखंड में 861 और बिहार में 354 लोग मधुमेह से पीड़ित पाए गए।

उच्च रक्तचाप : मध्यप्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर 768 (शहरों में 1580), उत्तरप्रदेश में 643 (शहरों में 976), राजस्थान में 644 (शहरों में 1166), झारखंड में 789 (शहरों में 1856), उड़ीसा में 1373 (शहरों में 2477), छत्तीसगढ़ में 613 (शहरों में 1577), उत्तराखंड में 1248 (शहरों में 2219) और बिहार में 757 लोग (शहरों में 1061) इससे पीड़ित पाए गए। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में यह बीमारी शहरी क्षेत्रों में 2 से 3 गुना ज्यादा विस्तार रखती है।

अस्थमा या श्वांस की स्थाई बीमारी : मध्यप्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर 448 लोगों को यह बीमरी है। उत्तरप्रदेश में 735, राजस्थान में 706, झारखंड में 415, उड़ीसा में 650, छत्तीसगढ़ में 460, उत्तराखंड में 839 और झारखंड में 1115 लोगों को यह स्थायी बीमारी है।

तपेदिक या टीबी : मध्यप्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर 145, उत्तरप्रदेश में 373, राजस्थान में 210, झारखण्ड में 320, उड़ीसा में 178, छत्तीसगढ़ में 207, उत्तराखंड में 237, बिहार में 330 लोग इसकी चपेट में हैं।

लंबी और स्थायी बीमारियों की स्थिति में उपचार के सन्दर्भ में व्यवहार : वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण बताता है कि स्थायी और लंबी गंभीर बीमारी की स्थिति में मध्यप्रदेश में 60.5 प्रतिशत लोग किसी न किसी स्रोत से उपचार करवा रहे हैं, या सरकारी स्रोत से 26.3 प्रतिशत लोग उपचार ले रहे हैं। उत्तरप्रदेश में 65.8 प्रतिशत (13 प्रतिशत सरकारी स्रोत से), राजस्थान में 66.2 प्रतिशत (50.3 प्रतिशत सरकारी स्रोत से), झारखंड में 55.5 प्रतिशत (14.8 प्रतिशत सरकारी स्रोत से), उड़ीसा में 62.6 प्रतिशत (52.7 प्रतिशत सरकारी स्रोत से), छत्तीसगढ़ में 53.7 प्रतिशत (27.4 प्रतिशत सरकारी स्रोत से), उत्तराखंड में 68.3 प्रतिशत (30.1 प्रतिशत सरकारी स्रोत से) और बिहार में 49.6 प्रतिशत (8.5 प्रतिशत सरकारी स्रोत से) लोग उपचार करवा रहे हैं।

यहां एक बात साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि लंबी और स्थायी बीमारियों की स्थिति में आधे लोगों को ही किसी न किसी तरह का उपचार हासिल हो पाता है। सरकारी स्रोतों तक लोगों की पहुंच और कम है।

बीमारी (एक लाख की जनसंख्या पर)	राज्य	मध्यप्रदेश अनुपात/लाख	मध्यप्रदेश में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	उत्तरप्रदेश अनुपात/लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	उत्तरप्रदेश में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	राजस्थान अनुपात/लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	राजस्थान में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	झारखंड अनुपात/ लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	झारखण्ड में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)
डायरिया	कुल	728	528528	792	1456000	420	288120	371	122430
	ग्रामीण	836	439736	831	1288050	408	210120	369	92250
	शहरी	500	100000	655	294750	455	77805	376	30080
तीव्र श्वसन संक्रमण	कुल	1572	1141272	6362	12724000	1186	813596	3142	1036860
	ग्रामीण	1538	808988	6242	9675100	1185	610275	2955	738750
	शहरी	1645	329000	6781	3051450	1188	203148	3678	294240
किसी भी तरह का बुखार	कुल	6391	4639866	4352	8704000	2776	1904336	3390	1118700
	ग्रामीण	7314	5309964	4523	7010650	3116	1604740	3593	898250
	शहरी	4444	888800	3754	1689300	1746	298566	2811	224880
किसी भी तरह की तीव्र बीमारी से पीड़ित लोग	कुल	9177	6662502	12050	24100000	5300	3635800	7397	2441010
	ग्रामीण	10202	5366252	12164	18854200	5655	2912325	7406	2443980
	शहरी	7016	1403200	11649	5242050	4224	722304	7372	589760

बीमारी (एक लाख की जनसंख्या पर)	राज्य	मध्यप्रदेश अनुपात/लाख	मध्यप्रदेश में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	उत्तरप्रदेश अनुपात/लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	उत्तरप्रदेश में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	राजस्थान अनुपात/लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	राजस्थान में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	झारखंड अनुपात/ लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	झारखण्ड में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)
तीव्र बीमारी से पीड़ित किसी भी स्रोत से इलाज करवा रहे हैं? (%)	कुल	92.5%		98.1%		95.8 %		89.2%	
	ग्रामीण	91.5%		98.0%		95.9 %		88.4%	
	शहरी	95.6%		98.4%		95.2 %		91.2%	
सरकारी स्रोत से इलाज करवाने वाले तीव्र बीमारी से पीड़ित लोग (%)	कुल	18.7%		4.6%		39.9 %		9.7%	
	ग्रामीण	19.1%		4.5%		40.2 %		9.3 %	
	शहरी	17.6%		5.0%		38.6 %		10.7%	
लंबी/स्थायी बीमारी के लक्षण वाले लोग	कुल	6736	4890336	9745		4327	2968322	7856	2592480
	ग्रामीण	6631	3487906	10307		4365	2247975	7053	1763250
	शहरी	6958	1391600	7777		4211		10156	812480

बीमारी (एक लाख की जनसंख्या पर)	राज्य	मध्यप्रदेश अनुपात/लाख	मध्यप्रदेश में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	उत्तरप्रदेश अनुपात/लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	उत्तरप्रदेश में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	राजस्थान अनुपात/लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	राजस्थान में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	झारखंड अनुपात/ लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	झारखण्ड में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)
लंबी/स्थायी बीमारी के लक्षण वाले लोगों का प्रतिशत, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा ली	कुल	80.8%		94.6 %		87.5 %		78.3 %	
	ग्रामीण	76.4%		94.4 %		86.2 %		73.2 %	
	शहरी	89.6%		95.3 %		91.7 %		88.4 %	
लंबी/स्थायी बीमारी डायबिटीज	कुल	385	279510	414	828000	345	236670	683	225390
	ग्रामीण	172	90472	295	457250	175	90125	332	83000
	शहरी	834	166800	829	373050	861	147231	1688	135040
लंबी/स्थायी बीमारी हायपरटेंशन या उच्च रक्तचाप	कुल	768	557568	643	1306000	644	441784	789	260370
	ग्रामीण	383	201458	548	849400	472	243080	417	137610
	शहरी	1580	316000	976		1166	199386	1856	148480
लंबी/स्थायी बीमारी तपेदिक या टीबी	कुल	145	105270	373	746000	210	144060	320	105600
	ग्रामीण	149	78374	396	613800	231	118965	353	88250
	शहरी	137	26800	292	131400	148	25308	226	2080

बीमारी (एक लाख की जनसंख्या पर)	राज्य	मध्यप्रदेश अनुपात/लाख	मध्यप्रदेश में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	उत्तरप्रदेश अनुपात/लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	उत्तरप्रदेश में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	राजस्थान अनुपात/लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	राजस्थान में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	झारखंड अनुपात/ लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	झारखण्ड में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)
अस्थमा/स्थायी श्वास की बीमारी	कुल	448	325248	735	1470000	706	484316	415	136950
	ग्रामीण	443	321618	782	1212100	777	400155	382	95500
	शहरी	457	331782	572	257400	490	83790	509	40720
आर्थ्राइटिस या गठिया	कुल	858	622908	1311	2622000	508	348488	1196	394680
	ग्रामीण	828	435528	1415	2193250	524	269860	1183	295750
	शहरी	921	184200	944	424800	460	78660	1234	98720
जिनमें किसी लंबी/स्थायी बीमारी की पहचान हुई	कुल	5286	3837636	8384	16768000	4228	2900408	6578	2170740
	ग्रामीण	4726	2485876	8753	13567150	3996	2741256	5672	1418000
	शहरी	6468	1293600	7095	3192750	4931	843201	9173	733840
जो किसी लंबी/स्थायी बीमारी का खुद अपना इलाज करवा रहे हैं (%)	कुल	60.5%		65.8 %		66.2 %		55.5 %	
	ग्रामीण	54.1%		54.7 %		62.1 %		47.9 %	
	शहरी	70.3%		66.0 %		79.4 %		68.9 %	
जो किसी लंबी/स्थायी बीमारी का सरकारी इलाज करवा रहे हैं (%)	कुल	26.3%		13.0 %		50.3 %		14.8 %	
	ग्रामीण	25.6%		12.4 %		51.4 %		13.5 %	
	शहरी	27.5%		15.1 %		48.0 %		16.8 %	

बीमारी (एक लाख की जनसंख्या पर)	राज्य	उड़ीसा अनुपात/लाख	उड़ीसा में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	छत्तीसगढ़ अनुपात/लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	छत्तीसगढ़ में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	उत्तराखंड अनुपात/लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	उत्तराखंड में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	बिहार अनुपात/ लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	बिहार में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)
डायरिया	कुल	592	248640	903	230265	418	42218	1900	1972200
	ग्रामीण	630	220500	995	195020	428	29960	2095	1927400
	शहरी	399	27930	562	33158	395	12245	579	6369
तीव्र श्वसन संक्रमण	कुल	1252	525840	3396	865980	2000	202000	4199	4358562
	ग्रामीण	1348	471800	3201	627396	2007	170490	4290	3946800
	शहरी	757	52990	4110	242490	1983	61473	3582	39402
किसी भी तरह का बुखार	कुल	6403	2689260	6928	1766640	5843	590143	7421	7702998
	ग्रामीण	6542	2289700	6823	1337308	6104	427280	7701	7084920
	शहरी	5684	397880	7316	431644	5229	162099	5523	60753
किसी भी तरह की तीव्र बीमारी से पीड़ित लोग	कुल	9632	4045440	11646	2969730	8539	862439	14178	14716764
	ग्रामीण	9954	3483900	11386	2231656	8759	613130	14736	13557120
	शहरी	7965	557550	12603	743577	8023	248713	10397	114367

बीमारी (एक लाख की जनसंख्या पर)	राज्य	उड़ीसा अनुपात/लाख	उड़ीसा में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	छत्तीसगढ़ अनुपात/लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	छत्तीसगढ़ में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	उत्तराखंड अनुपात/लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	उत्तराखंड में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	बिहार अनुपात/ लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	बिहार में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)
अपने दम पर इलाज करवा रहे तीव्र बीमारी से पीड़ित लोग (%)	कुल	96.3%		98.3%		98.9%		98.2%	
	ग्रामीण	96.2%		98.0%		98.7%		98.2%	
	शहरी	96·9%		99·2%		99·3%		98·4%	
सरकारी स्रोत से इलाज करवाने वाले तीव्र बीमारी से पीड़ित लोग (%)	कुल	55·3%		30·6%		15·3%		4·8%	
	ग्रामीण	58·2%		30·0%		16·0%		4·8%	
	शहरी	36.7%		32.6%		13.7%		4.5%	
लंबी/स्थायी बीमारी के लक्षण वाले लोग	कुल	7254	3046680	4455	1136025	9821	991921	12003	12459114
	ग्रामीण	6981	2443350	4085	800660	9813	686910	12386	11395120
	शहरी	8666	606620	5812	342908	9840	305040	9407	103477
लंबी/स्थायी बीमारी के लक्षण वाले लोग, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा ली (%)	कुल	87·4%		85·7%		90·6%		85·4%	
	ग्रामीण	86·3%		83·2%		89·2%		84·9%	
	शहरी	91·7%		92·1%		94·7%		89·1%	

बीमारी (एक लाख की जनसंख्या पर)	राज्य	उड़ीसा अनुपात/लाख	उड़ीसा में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	छत्तीसगढ़ अनुपात/लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	छत्तीसगढ़ में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	उत्तराखंड अनुपात/लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	उत्तराखंड में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	बिहार अनुपात/ लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	बिहार में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)
लंबी/स्थायी बीमारी डायबिटीज	कुल	741	311220	595	151725	861	86961	354	367452
	ग्रामीण	516	180600	353	69188	506	35420	263	241960
	शहरी	1906	133420	1484	87556	1696	52576	969	10659
लंबी/स्थायी बीमारी हायपरटेंशन या उच्च रक्तचाप	कुल	1373	439360	613	156315	1248	126049	757	785766
	ग्रामीण	1160	406000	351	68796	834	58380	712	655040
	शहरी	2477	173390	1577	93043	2219	68789	1061	11671
लंबी/स्थायी बीमारी तपेदिक या टीबी	कुल	178	74760	207	52785	237	23937	330	342540
	ग्रामीण	187	65450	211	41356	235	16450	343	315560
	शहरी	130	9100	192	11328	242	7502	246	2706
लंबी/स्थायी बीमारी अस्थमा स्थायी श्वामस की बीमारी	कुल	650	273000	460	117300	839	84739	1115	1157370
	ग्रामीण	644	227500	436	85456	943	66010	1151	1058920
	शहरी	683	47810	550	32450	594	18414	872	9592
लंबी/स्थायी बीमारी आर्थ्राइटिस या गठिया	कुल	628	263760	627	159885	1929	194829	1764	1831032
	ग्रामीण	665	232750	633	124068	2187	153090	1817	1671640
	शहरी	441	154350	603	35577	1324		1406	15466

बीमारी (एक लाख की जनसंख्या पर)	राज्य	उड़ीसा अनुपात/लाख	उड़ीसा में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	छत्तीसगढ़ अनुपात/लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	छत्तीसगढ़ में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	उत्तराखंड अनुपात/लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	उत्तराखंड में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	बिहार अनुपात/ लाख (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)	बिहार में बीमार लोगों की संख्या (कुल पीड़ित/ जनसंख्या पर आंकलन)
लोगों की संख्या, जिनमें किसी न किसी तरह की लंबी/स्थायी बीमारी की पहचान हो चुकी है	कुल	6768	2842560	4093	1043715	9263	935563	9827	10200426
	ग्रामीण	6513	2279550	3511	688156	8864	620480	10012	9211040
	शहरी	8087	566090	6234	367806	10203	316293	8575	94325
स्थायी उपचार ले रहे वे लोग जिनमें किसी तरह की लंबी/स्थायी बीमारी की पहचान हुई (%)	कुल	62·6%		53·7%		68·3%		49·6%	
	ग्रामीण	59.6%		47.2%		63.5%		48.6%	
	शहरी	75.2%		67.3%		78.1%		56.0%	
सरकारी स्वास्थ्य स्रोत से स्थाई उपचार ले रहे लोग, जिनमें किसी तरह की लंबी/स्थायी बीमारी की पहचान हुई (%)	कुल	52·7%		27·4%		30·1%		8·5%	
	ग्रामीण	56·9%		30·2%		33·6%		8·2%	
	शहरी	36.2%		22.4%		23.2%		11.5%	

विकास संवाद

7/226, प्रथम तल, धनवंतरी काम्प्लेक्स के सामने, अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल 462016, मध्यप्रदेश

फोन – 0755 4252789

वेबसाईट – www.mediaforrights.org

ईमेल : vikassamvad@gmail.com